जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 323 प्रभात बीकानेर, रविवार 15 जून, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन अवरुद्ध होने के भय से ही ऑयल की कीमत में 14 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है

और अगर ''स्ट्रेट ऑफ होरमुज़'', जिसके मार्फत विश्व का 20 प्रतिशत ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, वाकई में अवरुद्ध हो गया तो ऑयल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर सौ से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकता है

- अभी ऑयल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से 80 डॉलर प्रति बैरल पहुँचने से ही भारत की इकॉनमी को भारी झटका लगा है, जिसे संभालने में ही पसीने छूट गये और अगर कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल हो गई तो भारत की इकॉनमी ''क्रैश'' होने की संभावना यथार्थ में परिवर्तित होगी।
- हालांकि, भारत ने पिछले कुछ वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल खरीदना काफी कम, लगभग बंद ही कर दिया था। भारत ''डिस्काउन्टेड कीमत'' पर, रूस से ऑयल खरीद रहा था, पर, ''डिस्काउन्टेड कीमत'' भी अंतर्राष्ट्रीय ऑयल प्रॉइस के अनुसार, घटती-बढ़ती तो है ही।
- अतः ऑयल प्रॉइस बढ़ने से देश में ट्रांसपोर्टेशन खर्च, पैकेजिंग खर्च, कृषि (खाद आदि) व कैमिकल्स की कीमत आसमान छूने लगेगी।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। इज़राइल और ईरान के बीच खुला संघर्ष छिड़ने से वैश्विक तेल बाज़ार अस्त-व्यस्त हो गया है। हालांकि अब तक किसी टैंकर पर हमला नहीं हुआ है और उत्पादन केंद्र भी सुरक्षित हैं, फिर भी केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव से ही कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हो गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 14 प्रतिशत बढ़ गयी है, और इसका मूल्य 70 डॉलर प्रति बैरल था, युद्ध शुरू होने के बाद 80 डॉलर के करीब पहुँच गया है।

इस मूल्य वृद्धि का कारण अभी तक तेल की कमी नहीं है, बल्कि बढ़ते जोखिम के कारण ऐसा हुआ है। इन आशंकाओं का मुख्य केंद्र है होरमुज़ की खाड़ी, जहाँ से विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान, चाहे वह ईरानी नाकेबंदी, माइंस लगाना हो या लक्षित हमले हों, कीमतों को तुरंत 100 डॉलर प्रति बैरल या उससे अधिक तक पहुँचा सकता है। वैश्विक कमोडिटी व्यापारी, शिपिंग बीमा कंपनियाँ और नीति निर्माता पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि एक भी चूक से तेल आपूर्ति व्यवस्था में अफरा तफरी मच सकती है।

भारत पर इसका प्रभाव सबसे जल्दी और बहुत गंभीर होगा। भारत अब भी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है, और हालाँकि ईरान से प्रत्यक्ष आयात हाल के वर्षों में अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते कम हुआ है, फिर भी हमारा देश वैश्विक तेल मूल्यों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के बजट घाटे को बढ़ाएंगी, रुपये को कमजोर करेंगी, और महंगाई बढ़ेगी। और वो भी तब ऐसे समय में जब देश कोविड के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

जयपुर, 14 जून। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर, उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त काजू उर्फ राजू कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग की सहमति के खिलाफ जाकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 7 फरवरी, 2023 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी गत 1 फरवरी को चावल खरीदने के लिए बाजार गई थी, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चला है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त ने उसे वैद्य जी का चौराहा

- पीड़िता का अपरहरण कर अभियुक्त उसे अहमदाबाद ले गया और कई बार दुष्कर्म किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान का महेश कुमार नीट-यूजी ऑल इंडिया टॉपर

हनुमानगढ़ के महेश कुमार ने 99.99 परसैंटाइल प्राप्त किए

- दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया व तीसरा स्थान महाराष्ट्र के कृषांग जोशी को मिला। लड़कियों में अविका अग्रवाल ने टॉप किया है।
- नीट यूजी परीक्षा चार मई को आयोजित की गई थी और इसमें 12.36 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं।
- इस वर्ष कट ऑफ में 18 अंकों की गिरावट देखी गई। सामान्य वर्ग की कट ऑफ 686-144 अंक के बीच है। ओबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ 143 से 113 के बीच है। जनरल वर्ग के दिव्यांग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की कट ऑफ 143 से 127 के बीच व एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के दिव्यांगों की कट ऑफ 126 से 113 अंक है।

नयी दिल्ली, 14 जून। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2025 का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया, जिसमें 12.36 लाख से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

इस साल राजस्थान के महेश कुमार ने 99.99 परसेंटाइल हासिल कर टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। वहीं, मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया को दूसरा स्थान और महाराष्ट्र के कृषांग जोशी को तीसरा स्थान मिला है। लड़कियों में अविका अग्रवाल ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं।

इस बार कटऑफ में 18 अंकों की कमी देखी गई। एनटीए ने नीट-यूजी 2025 के लिए ने सभी श्रेणियों के लिए कटऑफ स्कोर भी जारी किया है। इस वर्ष सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कटऑफ स्कोर 686 से 144 के बीच निर्धारित किया गया है। वहीं, जनरल श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह कटऑफ स्कोर 143 से 127 के बीच है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के लिए कटऑफ स्कोर 143 से 113 के बीच निर्धारित है। अनुसूचित जाति, जन जाति व ओबीसी के दिव्यांगों के लिए कट ऑफ 126 ये 113 के बीच है।

उल्लेखनीय है कि नीट-यूजी 2025 की परीक्षा चार मई को आयोजित की गई थी। परीक्षाएं देश के 552 शहरों के 5468 केन्द्रों पर 13 भाषाओं में आयोजित हुई थीं। देश के बाहर यह परीक्षा 14 शहरों में आयोजित की गयी, जिनमें आबू धाबी, दुबई, बैंकॉक, कोलंबो, दोहा, काठमांडू, कुआलालंपुर, कुवैत सिटी, लागोस, मनामा, मस्कट, रियाद, शारजाह और सिंगापुर शामिल हैं।

इस वर्ष 22 लाख 76 हजार 069 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जबकि कुल 22 लाख नौ हजार 318 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 12 लाख 36 हजार 531 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।

पिछले वर्ष नीट-यूजी 2024 में 24 लाख छह हजार 079 विद्यार्थी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जबकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इज़रायल-ईरान युद्ध से खाड़ी देशों में कार्यरत 72 लाख भारतीयों की आजीविका व जिन्दगी जुड़ी है

ये भारतीय नागरिक यू.ए.ई., सऊदी अरब, कतर व कुवैत में रहते और कार्य करते हैं

- इन भारतीयों की आजीविका, रेमिटैन्स, व सेफ्टी से भारत के सामाजिक, आर्थिक संतुलन का गहरा संबंध है।
- अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि इस युद्ध का कारण, ''ईरान की अनियंत्रित न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा'' है। पर, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विचारक मानते हैं, इज़रायल ने कहीं न कहीं वो ''रेड लाइन'' (लक्ष्मण रेखा) लांघ दी है, अपने आक्रमण से, जिससे एक निर्णायक क्षेत्रीय युद्ध की संभावना प्रबल हो गई है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। ईरान इज़रायल जंग के आर्थिक दुष्प्रभावों के अलावा, यूएई, सऊदी अरब, क़तर और कुवैत सहित, खाड़ी देशों में रहने वाले 72 लाख से अधिक भारतीयों पर भी इस बढ़ते तनाव का सीधा और अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता उनके रोज़गार व सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, जो भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस स्थिति को और बिगाड़ने में वैश्विक शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका की भूमिका पर भी विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इज़राइल की आक्रामक रणनीति का समर्थन करते हुए इसे ईरान की निरंकुश परमाणु महत्वाकांक्षाओं के प्रति आवश्यक प्रतिक्रिया बताया है।

हालांकि, कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इज़राइल की यह सैन्य कार्रवाई एक रेड लाइन पार कर चुकी है, जिससे ईरान की ओर से पलटवार की आशंका और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में खाड़ी अध्ययन के पूर्व अध्यक्ष प्रो. आफताब कमाल पाशा ने इज़राइल की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, ''वैश्विक शक्तियों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीज़फायर के बाद सीमावर्ती जिलों में किये तबादलों पर पुनर्विचार करें

जयपुर, 14 जून। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राज्य सरकार को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एएनएम का सीमावर्ती जिले में किए गए तबादला -आदेश पर नए सिरे से विचार किया जाए। पीठासीन अधिकारी चेतनराम देवड़ा और लेखराज तोसावडा ने ये आदेश कविता की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि भारत-पाकिस्तान के बीच गत दिनों सीमा पर तनाव हुआ था। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान, पाकिस्तान ने भी देश में हवाई हमले की कोशिश की थी। ऐसे में राज्य सरकार ने एहतियातन याचिकाकर्ता सहित अन्य लोगों का

- राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राज्य सरकार को आदेश दिये।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस पीढ़ी के युवा वकीलों से सुप्रीम कोर्ट को गंभीर शिकायत है

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि युवा वकील अपना करियर ट्रायल कोर्ट से शुरु नहीं करना चाहते

- इस कारण उन्हें कोर्ट की प्रक्रिया से पूरी वाकफियत नहीं होती।
- कोर्ट ने यह टिप्पणी पॉक्सो केस में दस साल की सजा भुगत रहे एक आरोपी की पैरोल याचिका की सुनवाई करते हुए की।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह चिंता व्यक्त की कि अब अधिकतर युवा वकील अपने करियर की शुरुआत ट्रायल कोर्ट से करने से बच रहे हैं, जिससे उन्हें मुकदमेबाज़ी की बुनियादी प्रक्रियात्मक (प्रोसीजरल) समझ विकसित करने का अवसर नहीं मिल पाता। अवकाशकालीन पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी ने टिप्पणी की, कि ''इस पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे प्रैक्टिस सीखने के लिए ट्रायल कोर्ट जाना ही नहीं चाहते।'' इस पीठ में न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले भी शामिल थे। यह टिप्पणी उस समय आई जब एक वकील को सुप्रीम कोर्ट में पैरोल याचिका से संबंधित प्रक्रिया समझानी पड़ी।

यह मामला पॉक्सो (बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण) अधिनियम के तहत 10 साल की सजा काट रहे एक दोषी की पैरोल याचिका से जुड़ा था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरोपी को सितंबर 2024 में उसकी पत्नी की सर्जरी के लिए 45 दिन की पैरोल पहले ही दी जा चुकी थी।

हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि उस समय हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उसकी पत्नी की सर्जरी नहीं हो सकी थी, और अब सर्जरी 16 जून को तय की गई है। वकील ने यह भी कहा कि सर्जरी के बाद पत्नी की देखभाल और नाबालिग बच्चों के पालन-पोषण के लिए आरोपी की उपस्थिति आवश्यक है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट बैंच ने अंततः 15 जून से 21 जून तक एक सप्ताह की पैरोल मंज़ूर कर दी, लेकिन पीठ ने याचिका दायर करने की प्रक्रिया को लेकर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले उचित प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क नहीं किया और न ही राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पूर्व सूचना दी।

कोर्ट ने वकील से कहा, ''मानक प्रक्रिया यही है कि पहले संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया जाए, कारणों को समझाया जाए, और फिर पैरोल आदेश प्राप्त किए जाएँ - लेकिन यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।''

एक सप्ताह की पैरोल देते हुए न्यायालय ने कहा, ''हम इस स्तर पर यह नहीं कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करना सही है या नहीं।''

जब याचिकाकर्ता के वकील ने राहत अवधि को दो सप्ताह तक बढ़ाने का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति भट्टी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश उनके साथी न्यायाधीश के आग्रह पर ही पारित किया गया है - यह संकेत देते हुए कि वे खुद इसे खारिज कर देते। हालांकि पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता आगे संबंधित अधिकारियों के समक्ष पैरोल एक्सटैंशन के लिए आवेदन दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का रुख फिर से कर सकता है।

राहुल गांधी के जन्मदिन पर रोजगार मेला

नयी दिल्ली, 14 जून। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर 19 जून को दिल्ली कांग्रेस पार्टी तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में पूर्वाह्न 10 बजे से एक मैगा जॉब फेयर आयोजित करेगी।

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने शनिवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि दिल्ली कांग्रेस और युवा कांग्रेस मिलकर 19 जून को तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में पूर्वाह्न 10 बजे से एक मैगा जॉब फेयर का आयोजन करेगी, जिसमें लगभग 100 प्रमुख कंपनियां 5000 से

- दिल्ली कांग्रेस 19 जून, राहुल गांधी के जन्मदिन पर तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में एक मैगा जॉब फेयर आयोजित करने जा रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस में जातिगत जनगणना के बारे में हिचकिचाहट सी क्यों है?

हालांकि, राहुल गांधी पूर्णतया, ''कास्ट सैन्सस'' के पक्ष में पुरजोर तरीके से हैं, पर, काफी कुछ पार्टी के पुराने वरिष्ठ नेताओं में बेचैनी सी है, इस जातिगत जनगणना को लेकर

- बेचैनी का कारण है, कांग्रेस का परम्परागत समर्थक वोट, सवर्ण वोट, इस ''कास्ट सैन्सस'' के नतीजों के बारे में आशंकित है तथा कांग्रेस की पुराने नेताओं को इस वोट बैंक के खिसकने का भय है।
- इन वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मतगणना के कारण ओबीसी आदि का आरक्षण बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। पर, इस आरक्षण बढ़ने का लाभ क्षेत्रीय पार्टियों को, जैसे, सपा, आरजेडी, बसपा, जेडी (यू) को ही मिलेगा, जो अधिकतर जात आधारित पार्टियाँ मानी जाती हैं।
- जानकार लोगों का यह भी कहना है कि 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक व जातिगत आधार पर जनगणना करवाई थी। पर, इस सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने दी थी, क्योंकि सर्वे का नतीजा शायद कांग्रेस के पक्ष में नहीं था।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा तो कर दी, लेकिन भाजपा के बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिन्तित हैं कि इससे हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा नष्ट हो जायेगी। इधर, कांग्रेस में भी जातिगत जनगणना को लेकर मिले-जुले विचार हैं तथा कुछ ग्रुपों की ओर से विपक्ष पर राजनैतिक, रणनीतिक तथा लॉजिस्टिक चिंताओं का आरोप लगाया जा सकता है। यहाँ हम उन प्रमुख कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग राहुल गांधी द्वारा समर्थित एवं प्रोत्साहित जाति गणना के विरोध में क्यों हैं या वे पूरी तरह इसका समर्थन करने में क्यों हिचक रहे हैं।

पहली बात कांग्रेस को परम्परागत रूप से कई राज्यों में अगड़ी जातियों, खासातौर से ब्राह्मणों का समर्थन मिलता रहा है। जातिगत जनगणना से घोर असमानताएं खुलकर सामने आ सकती हैं तथा आरक्षण को फिर से तय किये जाने की माँग उठ सकती है तथा इससे अगड़ी जातियों के मतदाता परेशान एवं नाराज़ हो सकते हैं।

दूसरी बात, कांग्रेस एक व्यापक-जनाधार वाला राजनैतिक संगठन है, जिसमें विभिन्न जातियों और राज्यों के नेता शामिल हैं। हाल ही के वर्षों में राहुल गांधी तथा कुछ अन्य नेताओं ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है तथा इसके पीछे ''सामाजिक न्याय'' की भावना रही है। लेकिन कुछ पुराने नेता इसलिये आशंकित एवं सतर्क हैं क्योंकि उन्हें कुछ जातियों के दूर हो जाने का डर है। इसके अलावा, वे इसे पार्टी की मूल विचारधारा के विरोध में मान रहे हैं।

कांग्रेस यह देखती आ रही है कि क्षेत्रीय दल जैसे आरजेडी, सपा, और जेडीयू ने जाति आधारित गठबंधनों से मजबूत राजनीतिक आधार तैयार किया है।

लेकिन कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों को डर है कि जाति जनगणना से वोट बैंक और भी ज्यादा बंट सकता है और इससे जाति-आधारित क्षेत्रीय दलों को फायदा हो सकता है।

इसके अलावा, जाति जनगणना की प्रक्रिया अपने आप में जटिल है, वर्गीकरण, गिनती और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में 20 जून को मानसून आएगा

जयपुर, 14 जून। भीषण गर्मी से जूझ रहे राजस्थानवासियों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार, राज्य में 20 जून के आसपास मानसून के प्रवेश की प्रबल संभावना है। इस दिशा में संकेत पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक

- भारतीय मौसम विभाग ने तेज बारिश के संकेत दिए और कहा, 14 जून से जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर व भरतपुर में बादल छाने, आँधी व छिटपुट बारिश की संभावना है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK